भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 870

(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक), को दिया जाना है)

आर्थिक अवमूल्यन

870. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2020 में रुपये का प्रदर्शन सभी एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोविड से होने वाली मृत्यु के समान पैटर्न वाले सभी पड़ोसी देशों में भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ने के क्या कारण हैं जबकि इस महामारी ने सभी देशों को प्रभावित किया है;

(घ) क्या प्रति मिलियन जनसंख्या मृत्यु दर और आर्थिक अवमूल्यन दोनों को देखते हुए कोविड का सभी एशियाई देशों की तुलना में भारत पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार इस संकट में क्यों नहीं बच सकी?

(ग) मांग और खपत को पुनरूज्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम और प्रस्तावित प्रोत्साहन कौन-कौन से हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रुपया 2020 में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में से एक था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारतीय रुपये में 02 फरवरी, 2021 तक 3.53 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हुई है।

(ग) भारत ने अन्य प्रमुख एशियाई देशों की तुलना में अप्रैल-जून 2020 के दौरान, अत्यधिक कठोर लॉकडाउन लागू किए थे। जीडीपी में गिरावट कठोर लॉकडाउन के प्रभाव के अनुरूप है।

(घ) और (ड.) कठोर लॉकडाउन उपायों के कारण, भारत कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर को महत्वपूर्ण रूप से रोकने में समर्थ रहा है। देश में क्रमिक रूप से अनलॉकिंग की प्रक्रिया के साथ, अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वी-आकार की रिकवरी हुई है।

वित्त वर्ष 2020-21 में, सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने तथा पुन: आर्थिक वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की राशि वाले आरबीआई द्वारा लिए गए मानदंड, जो भारत के जीडीपी के 13 प्रतिशत से अधिक है, कोविड-19 महामारी के प्रभाव से मुकाबला करने के लिए आर्थिक वृद्धि का पुनरूद्धार करना। इस पैकेज में, घरेलू मांग के लिए अन्य के साथ-साथ कोई वस्तु तथा नकद अंतरण राहत मानदंड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत रोजगार प्रावधान मानदंड, एमजीएनआरईजीएस के तहत बढ़ा हुआ आवंटन, एमएसएमई तथा एनबीएफसी और विनियामक एवं अनुपालन मानदंडों के लिए क्रेडिट गारंटी तथा इक्विटी निवेश-आधारित राहत उपाय शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में संरचनात्मक सुधारों की भी घोषणा की गई थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का अविनियमन, एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन, नई पीएसयू नीति, कोयला खदानों का वाणिज्यीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में उच्च एफडीआई सीमा, औद्योगिक भूमि/लैंड बैंक और औद्योगिक सूचना प्रणाली का विकास, सामाजिक अवसंरचना हेतु व्यवहार्यता अंतराल निधियन योजना में सुधार, नई विद्युत प्रशुल्क नीति और क्षेत्र सुधारों को आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

*****